

रजिस्टर्ड नं० एल०-३३/एस०एम०/१३-१४/९६.



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, वीरवार, १ अगस्त, १९९६/१० श्रावण, १९१८

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी (अंग्रेजी) अनुभाग

अधिसूचना:

शिमला-२, १ अगस्त, १९९६

संख्या एल० एल० अर० डी० (६) १८/९६-लैजिस्लेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद, २१३ के खण्ड (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख २६ जुलाई,

1996 को प्रस्थापित हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अध्यादेश, 1996 (1996 का अध्यादेश सख्यांक 2) का, संविधान के अनुच्छेद 348 के (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ साहित, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, \*

हस्ताक्षरित/-  
सचिव (विधि) ।

1996 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2.

**हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन  
अध्यादेश, 1996**

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा मत्र में नहीं है और राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है,

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा ( भत्ते और पेंशन) संशोधन अध्यादेश, 1996 है। संक्षिप्त नाम

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(i) खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थातः—

“(घ घ) “अकानूनी निकाय” से कानूनी निकाय से भिन्न व्यक्तियों का कोई निकाय अभिप्रेत है,” और

(ii) खण्ड (च) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थातः—

“(च च) “कानूनी निकाय से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित कोई निगम, समिति आयोग, परिषद, बोर्ड या व्यक्तियों का अन्य निकाय चाहे वह निगमित है या नहीं अभिप्रेत है,” और ।

3. मूल अधिनियम की धारा 6-घ के पश्चात, निम्नलिखित धारा 6-ड अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थातः— धारा 6-ड का अन्तः स्थापन।

“6-ड कतिपय सदस्य वेतन, पारिश्रमिक, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे:—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य जो किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में, किसी कानूनी

या अकानूनी निकाय से कोई वेतन, पारिवारिक, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार है, इस अधिनियम के अधीन उन्हें प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। ”

महावीर प्रसाद,  
राज्यपाल,  
हिमाचल प्रदेश ।

शिमला : 26-7-1996  
कुलदीप चन्द सूद,  
सचिव (विधि) ।

---

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. Ordinance No. 2 of 1996.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT  
ORDINANCE, 1996

AN

ORDINANCE

*further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).*

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Forty-Seventh Year of the Republic of India.

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in Session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

(1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Ordinance, 1996.

Short ti

(2) In section 2 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter called the principal Act)—

Amendm  
of sectic  
2.

(i) after clause (d), the following clauses shall be added, namely:—

“(dd) “non-statutory body” means any body of persons other than a statutory body ;” and

(ii) after clause (f) the following clauses shall be added, namely:—

“(ff) “statutory body” means any corporation, committee, commission, council, board, or other body of persons, whether incorporated or not, established by or under any law for the time being in and”.

(3) After section 6-D of the principal Act, the following Section 6-E shall be inserted, namely:—

“6-E. *Certain members not entitled to receive salary, remuneration, allowances and other facilities.*— Notwithstanding anything

contained in this Act, a member, who being the Chairman or the Vice Chairman of a statutory or non-statutory body, is entitled to receive any salary, remuneration, allowances and other facilities from any statutory or non statutory body, shall not be entitled to receive the same under this Act."

MAHABIR PARSAD,  
*Governor,*  
*Himachal Pradesh.*

Shimla : 26-7-1996.

K. C. SOOD,  
*Secretary (Law).*